



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 नवम्बर, 2023 ई0 (कार्तिक 13, 1945 शक सम्वत्) [संख्या-44

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	851-853	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	471-488	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	09-11	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	45-48	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	611-613	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

शहरी विकास अनुभाग-3

अनन्तिम अधिसूचना

25 अक्टूबर, 2023 ई0

संख्या 164106/IV(3)/2023-11(02 निर्वा0)/2022-उत्तराखण्ड की नगर पंचायत कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा-11क एवं 11ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिये आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो, तो वह लिखित रूप में जिलाधिकारी, नैनीताल को प्रेषित की जायेगी। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिनों के भीतर प्राप्त होगी।

प्रस्तावित अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा-11क एवं 11ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पंचायत, कालाढूंगी क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं :-

- (1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पंचायत क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।
- (2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 में उल्लिखित किया गया है।

नगर पंचायत कालाढूंगी जनपद नैनीताल

क्र0 स0	वार्ड/कक्ष का नाम	वार्ड/कक्ष की सीमा	वार्ड/कक्ष में सम्मिलित मोहल्लों का नाम
01	02	03	04
1-	जिम कार्बेट वार्ड	पूरब- मैथीसाह नाला पश्चिम-बौर नदी उत्तर- सिंचाई नहर दक्षिण- मैथीसाह नाला	डाक बंगला, कार्बेट म्यूजियम, हल्द्वानी छोटी

01	02	03	04
2-	फैक्ट्री वार्ड	पूरब- जी.जी.आई.सी की दीवार/अम्बेडकर पार्क पश्चिम-नैनीताल मोटर मार्ग उत्तर- सिंचाई नहर एवं जंगलात दक्षिण- रामनगर हल्द्वानी मोटर मार्ग	नौतिया फार्म, पालीटेक्निक मार्ग, आयरन फाउन्ड्री, काडीबेल
3-	बंजारा वार्ड	पूरब-धापला सड़क पश्चिम-जी.जी.आई.सी. के बगल में अम्बेडकर पार्क वाली गली उत्तर- जंगलात दक्षिण- रामनगर-हल्द्वानी मोटर मार्ग	बंजारा बस्ती, गांधी पार्क
4-	अस्पताल वार्ड	पूरब-जंगलात पश्चिम- धापला सड़क उत्तर- जंगलात दक्षिण-बाल्मिकी बस्ती की सड़क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्लाटर हाउस, सहकारी समिति
5-	तहसील वार्ड	पूरब-जंगलात एवं जी.आई.सी की दीवार पश्चिम- बडौदा बैंक के सामने की सड़क उत्तर- बाल्मिकी बस्ती की सड़क दक्षिण-थाना/उपकोषागार की सड़क	तहसील कालोनी, थाना, जी.आई.सी. बाल्मिकी बस्ती, रामलीला भवन
6-	मंगोलिया घड़ा / बाजार वार्ड	पूरब-जंगलात पश्चिम-मैथीसाह नाला उत्तर-रामनगर-हल्द्वानी मोटर मार्ग दक्षिण- बन्दोबस्ती वार्ड की सीमा	बाजार क्षेत्र, मंगोलिया घड़ा, शिवमन्दिर, मस्जिद, इदगाह, शिशु मन्दिर क्षेत्र
7-	बन्दोबस्ती वार्ड	पूरब- जंगलात/पूरनपुर ग्राम की सड़क पश्चिम- बौर नदी उत्तर-बाजार वार्ड की सीमा दक्षिण- चांदनी चौक की सीमा	कालादूंगी बन्दोबस्ती, हुडकिया चौड़, हनुमान मन्दिर

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार शुक्ल,

उप सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 नवम्बर, 2023 ई0 (कार्तिक 13, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज़ाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

18th October, 2023

Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Green Energy Open Access) Regulations, 2023

No. F-9 (35)/RG/UERC/2023/779 - In exercise of the powers conferred by Section 181, read with section 39, 40, 42 and 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby proposes to make the following Regulations, namely:

1. Short Title, Commencement and Interpretation:

- (1) These Regulations shall be called Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Green Energy Open Access) Regulations, 2023.
- (2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Government Gazette.

2. Definitions and Interpretation:

1. In these regulations, unless the context otherwise, requires:
 - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (b) "Banking" means the surplus green energy injected in the grid and credited with the distribution licensee by the Green Energy Open Access consumer and that shall be drawn by such consumer along with charges to compensate additional costs if any;
 - (c) "Billing Cycle" means the period as approved by the Commission for which regular electricity bills are to be prepared by the Licensee for different categories of consumers;
 - (d) "Central Nodal Agency" means the nodal agency as specified by the Central Government as per the rules;
 - (e) "CERC" means the Central Electricity Regulatory Commission;
 - (f) "Commission" means the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission;
 - (g) "Day Ahead Market (DAM)" means a market where Day Ahead Contracts are transacted on the Power Exchange(s);
 - (h) "DSM Regulations" means the UERC (Deviation Settlement Mechanism & Related Matters) Regulations, 2017 and any subsequent amendments thereafter;
 - (i) "Forum of Regulators (FOR)" means the forum as referred to in sub-section (2) of section 166 of the Act;
 - (j) "Fossil Fuel" means fuels such as coal, lignite, gas, liquid fuel or a combination of these as its primary source of energy, which are used in thermal generating stations for generating electricity;
 - (k) "GOAR Portal" means the Green Open Access Registry Portal, which is a single window portal to register and apply for the Green Energy Open Access;
 - (l) "Green energy" means the electrical energy from renewable sources of energy including hydro and storage (if the storage uses renewable energy) energy from non-fossil fuel-based Waste-to-Energy plant or any other technology as may be notified by the Central Government from time to time

and shall also include any mechanism that utilizes green energy to replace fossil fuels including production of green hydrogen or green ammonia as may be determined by the Central Government;

- (m) "Green Energy Open Access customer (in short "customer")" means a consumer, trader, distribution licensee or a generating company who has been granted Green Energy Open Access under these regulations;
- (n) "IEGC" means the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023 and any subsequent amendments thereafter;
- (o) "Non-Peak Hours" means hours other than Peak hours as may be decided by the Commission from time to time.
- (p) "Rules" means the Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access) Rules, 2022 and any subsequent amendments thereafter;
- (q) "Standby Charges" means the charges applicable to green energy open-access customer against the standby arrangement provided by the distribution licensee, in case such green energy open access customer is unable to procure/schedule power from the generating sources with whom they have the agreements to procure power due to outages of generator, transmission systems and the like;
- (r) "State Grid Code" means the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations, 2016 and any subsequent amendments thereafter;
- (s) "Supply Code" means the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (The Electricity Supply Code, Release of New Connection & Related Matters) Regulations, 2020 and any subsequent amendments thereafter;
- (t) "Time Block" means a time block of 15 minutes for which specified electrical parameters and quantities are recorded by special energy meter, with first time block starting at 00.00 hrs;

Words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act or the other Regulations issued by the Commission shall have the same

meaning assigned to them respectively in the Act or such Regulations issued by the Commission.

3. Scope:

These Regulations shall be applicable for allowing connectivity and open access to green energy open access customers for use of Intra-state transmission system (IaSTS) or Distribution system or both including when such system is used in conjunction with inter-State transmission system.

Provided that a generating station, including a captive generating plant, or a consumer shall not be eligible to apply for long-term or medium-term or short-term open access unless he has the connectivity or he applies for connectivity to the intra-State transmission or distribution system as the case may be.

Provided further that a person may apply for connectivity as well as long term or medium term or short-term open access simultaneously.

Provided also that other conditions of grant of connectivity and open access in respect of green energy generation, purchase and consumption, to which no express provision has been made in these regulations, shall be in accordance with the provisions of Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Intra-State Open Access) Regulations, 2015, UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2018 and Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2017, and any subsequent amendments thereafter.

4. Eligibility criteria for Green Energy Open Access:

The consumer who has contracted demand or sanctioned load of 100 kW or more, either through a single connection or through multiple connections in the name of same consumer aggregating 100 kW or more located in the same electricity division of a distribution licensee, shall be eligible to take power through Green Energy Open Access and there shall be no limit for other customers including Captive consumers, RE generators etc., drawing/supplying power under Green Energy Open Access.

Provided that the customer shall compulsorily maintain the approved capacity/schedule for atleast 12 time blocks in a day.

Provided further that any deviation from approved capacity/schedule shall be subject to charges as per UERC DSM Regulations.

5. Nodal Agency:

State Load Despatch Centre (SLDC) Uttarakhand shall be the Nodal Agency for grant of Green Energy Open Access for short-term (upto one month) and the State Transmission Utility (STU) shall be the Nodal Agency for grant of Green Energy Open Access for Medium-term (a period exceeding three months but not exceeding three years) and long-term (a period exceeding 12 years but not exceeding 25 years).

6. Procedure for grant of Green Energy Open Access:

- (1) A detailed procedure for the grant of connectivity for Green Energy Open Access including the application format and applicable Bank Guarantees/Fee/Charges etc. shall be prepared by the Nodal agency within a period of 30 days from the date of notification of these regulations and submit the same to the Commission for approval.
- (2) All the applications for registration of the Green Energy Open Access complete in all respects, shall be submitted on the portal setup by the Central Nodal Agency and these applications shall get routed to SLDC.
- (3) SLDC shall process and recommend the applications for registration of the Green Energy Open Access within 5 working days for new applications and within 2 working days for renewal of registration through the GOAR Portal.

Provided that after the receipt of the application for registration, SLDC, shall conduct a preliminary scrutiny to ensure application is complete in all respects. In case of any discrepancy/shortcoming/ requirement of any further information, SLDC shall intimate the applicant through the portal for rectification of the deficiency within a period of 2 working days. In case the applicant does not respond within a period of 2 working days with the required details to SLDC, the registration request shall be disposed of.

- (4) An application for availing Green Energy Open Access can be made through the GOAR portal only by the registered customers.

- (5) The concerned Nodal Agency shall approve the application for availing Green Energy Open Access of the registered customers within a period of 15 working days from the date of application, failing which it shall be deemed to have been approved.

Provided that the order of processing of such applications for Green Energy Open Access shall be first in first out.

- (6) Short-term and Medium-term open access shall be allowed if there is sufficient spare capacity available in the transmission system without any augmentation whereas for Long-term open access, the transmission system may be augmented if required.

Provided that priority shall be given to long-term access in the existing system if spare capacity is available and further, open access for non-fossil fuel sources shall be given priority over the open access from the fossil fuel.

- (7) No application for open access shall be denied unless the applicant has been given an opportunity of being heard in the matter by the Nodal Agency and all orders denying open access shall be speaking orders.
- (8) Appeals against an order of the Nodal Agency, shall lie before the Commission, within a period of thirty days from the date of receipt of an order under sub-Regulation (7) above.
- (9) The Commission shall dispose of the appeal within a period of three months and the order issued by it shall be binding on the parties.

7. Metering:

Green Energy Open Access customers shall comply with the metering requirements laid down in the CEA (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 as amended from time to time and also included in State Metering Communication & Data Acquisition Requirements (MCDAR) specified under State Grid Code.

8. Green Energy Open Access Charges:

- (1) The charges to be levied on Green Energy Open Access customers shall be as follows:
- a) Transmission charges;

- b) Wheeling charges;
- c) Cross subsidy Surcharge;
- d) Standby charges wherever applicable;
- e) Banking charges; and
- f) Application fees/SLDC fees/Charges, scheduling charges, deviation settlement charges and reactive energy charges.

The methodology for calculation of Transmission, Wheeling and Cross subsidy Surcharge charges shall be as specified in the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions of Intra-State Open Access) Regulations, 2015 as amended from time to time.

Further, Scheduling and Deviation Mechanism shall be governed by State Grid Code and DSM Regulations as amended from time to time.

Provided that the cross-subsidy surcharge for Green Energy Open Access Consumers purchasing green energy, from a generating plant using renewable energy sources, shall not be increased, during twelve years from the date of operating of the generating plant (using renewable energy sources), by more than fifty percent of the surcharge fixed for the year in which open access is granted.

Provided further that such cross subsidy surcharge shall not be levied in case distribution access is provided to a person who has been availing green power from the plant established as a captive generation plant for his own use.

Provided also that no additional surcharge shall be applicable on embedded consumers of distribution licensee who opt for Green Energy Open Access.

Provided also that cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable in case power produced from a non-fossil fuel-based Waste-to-Energy plant is supplied to the Open Access Consumer.

Provided also that cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable if green energy is utilized for production of green hydrogen and green ammonia.

Provided also that additional surcharge shall not be applicable in case electricity is produced from offshore wind projects, which are commissioned upto December,2032 and supplied to the Open Access Consumers.

Provided also that levy of Open Access Charges shall be governed by the relevant provisions of the Act and the Policies issued by Central/State Government from time to time.

- (2) The "Standby Charges" shall be as specified in the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions of Intra-State Open Access) Regulations, 2015 as amended from time to time and such charges shall not be applicable if the Green Energy Open Access Customer has given notice in writing, in advance at least a day in advance before closure time of the Day Ahead Market on 'D-1' day; 'D' being the day of delivery of power for standby arrangement to the distribution licensee.
- (3) **Reactive Energy Charges:** The Green Energy Open Access customer shall pay for the reactive energy in accordance with provisions of the State Grid Code notified by the Commission.
- (4) **Collection of Charges:** The Charges in respect of Green Energy Open Access customers shall be payable directly to the Nodal Agency and Distribution licensee in accordance with the terms and conditions of payment specified by the Nodal Agency.

9. Banking Facility and Charges:

- (1) Banking facility shall be provided to the consumer availing Green Energy Open Access. The surplus energy from a Green Energy generating station after setoff shall be banked with the Distribution Licensee.
- (2) The banking facility including injection of surplus energy and drawal of banked energy shall be subject to scheduling.
- (3) The Banking Charges shall be adjusted in kind @ 8% of the energy banked.
- (4) The permitted quantum of banked energy by Green Energy Open Access consumer shall be atleast 30% of its total monthly consumption of electricity from the Distribution Licensee.

- (5) The Banking of energy shall be permitted only for the billing cycle:

Provided that the credit for banked energy shall not be permitted to be carried forward to subsequent billing cycles and the credit for energy banked shall be adjusted during the same billing cycle.

Provided further that, the energy banked during peak hours (TOD slots) shall be permitted to be drawn during peak as well as non-peak hours (TOD slots) by paying banking charges as specified in sub-Regulation (3) above.

Provided also that, the energy banked during non-peak hours (TOD slots) shall be permitted to be drawn during non-peak hours (TOD slots) by only paying the banking charges and from non-peak hours (TOD slot) to peak hours (TOD slot) by paying charges in kind @ equivalent to % of difference between the Peak hours energy charge rate and Normal hours energy charge rate (as defined in the respective Tariff Orders issued by the Commission) of the energy banked in addition to the above banking charges as specified in sub-Regulation (3) above.

- (6) The un-utilized surplus banked energy shall be considered as lapsed at the end of each billing cycle. However, the RE Generating Station would be entitled to Renewable Energy Certificates to that extent.
- (7) The Distribution licensee shall prepare a detailed procedure for banking along with model banking agreement within a period of 30 days of the notification of these regulations. The energy accounts of all banking transactions shall be maintained by Distribution Licensee and shall be submitted to SLDC on weekly basis.

10. Energy Losses:

Energy losses of the transmission and distribution system shall be applicable to the Green Energy Open Access customers as specified by the Commission from time to time.

11. Compliance with State Grid Code/Supply Code:

Green Energy Open Access customers shall abide by the State Grid Code, Supply Code and all other Codes and Standards, DSM Regulations as applicable from time to time.

12. Curtailment Priority:

In case due to constraints in the transmission system or distribution system, the curtailment priority shall be as follows:

- (a) Short-term open-access customers other than Green Energy Open Access customers shall be curtailed first followed by Green Energy Open Access customers.
- (b) Next, Medium-term open-access customers other than Green Energy Open Access customers shall be curtailed first followed by Green Energy Open Access customers.
- (c) Next, Long-term open-access customers other than Green Energy Open Access customers shall be curtailed first followed by Green Energy Open Access customers.

Provided that within a category, the Green Energy Open Access consumers shall have equal curtailment priority and shall be curtailed on pro-rata basis.

Provided further that distribution licensees shall be curtailed as last resort.

13. Power to relax:

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

14. Power to amend:

The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend, or repeal any provisions of these Regulations.

15. Power to remove difficulties:

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by an order, make such provisions, not inconsistent to the provisions of the Act and these Regulations, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

By Order of the Commission,

NEERAJ SATI,

Secretary,

Uttarakhand Electricity Regulatory Commission.

निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड

27 अक्टूबर, 2023 ई०

संख्या 697 / 933 / जि०प०अ०को० / 2022-23-

जिला पंचायत चम्पावत द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम सं०-11, वर्ष 2016) के भाग-4 की धारा 106, के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, चम्पावत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिबन्धित एकल उपयोग प्लास्टिक उपविधि-2022, को प्रस्ताव संख्या-03 दिनांक 13.04.2023 द्वारा जनपद चम्पावत के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत प्रतिबन्धित एकल उपयोग प्लास्टिक उपविधि-2022 निर्मित की गई हैं।

कार्यालय जिला पंचायत, चम्पावत

यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर जिला पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रूप में आपत्ति दर्ज कराये निर्धारित समय के उपरान्त आपत्ति प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्धित एकल उपयोग प्लास्टिक (Single use plastic) उपविधि 2022

कार्यालय जिला पंचायत चम्पावत के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रयोग प्रतिबन्धित करने के लिए बनायी गई उपविधियाँ/उपनियम-

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में दी गई धारा 106 में जिला पंचायतों के प्रयोजन के लिये ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिनका उपविधियों द्वारा शासित होना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है जो जिले के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सुविधा समुन्नती अनुरक्षण के प्रयोजन हेतु एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबन्धित करने के लिए जनपद चम्पावत के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु उपविधियाँ / उपनियम का निर्माण किया जाता है, जिसमें शासनादेश संख्या 182/XII(1)2017-70(08) 2017 रिट दिनांक 24.10.2017 द्वारा उत्तराखण्ड की पंचायतों हेतु ठोस प्रबन्धन नीति 2017 प्रख्यापित की गई। इसके प्रावधानों एवं रिट याचिका संख्या 93/2022 (पी०आई०एल०) जितेन्द्र यादव बनाम भारत संघ एवं अन्य में मा० न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश व दिनांक 08.09.2022 को मा० मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालनार्थ एवं उपविधियाँ निर्मित की जाती है।

उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों का निस्तारण करने उपरान्त जिला पंचायत चम्पावत की सामान्य बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए, प्रतिबन्धित एकल उपयोग प्लास्टिक उपविधि 2022 लागू करने की कार्यवाही की जायेगी। यह उपविधि जिला पंचायत में गजट नोटिफिकेशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। तथा यह प्रतिबन्धित एकल उपयोग प्लास्टिक उपविधि 2023 कहलायेगी।

1- कोई भी व्यक्ति स्वयः या किसी और के माध्यम से जानबूझकर या अनजाने में निम्नलिखित प्लास्टिक/थर्मकोल/स्टायरोफोम सामान के क्रय विक्रय, उत्पादन, आयात, भण्डारण, ले जाना व उपयोग व आपूर्ति जनपद चम्पावत के सीमान्तर्गत नहीं करेगा।

(क) किसी भी आकार मोटाई, मॉप व रंग के प्लास्टिक कैरी बैग (हैंडिल के साथ अथवा बिना हैंडिल के साथ) और नान वोवन पॉली प्रोपाईलिन बैग परन्तु बायो कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग एवं 75 (उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये जाने वाले परिवर्तन के अनुसार परिवर्तनीय) माईक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट व ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट परिवहन में उपयोग किये जाते हैं, पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(ख) थर्मकोल (पॉलिस्टायरीन) पालीयूरेथिन, स्टायरोफोम, और इसी तरह के बने एकल उपयोग के लिए डिस्पोजैबल, कटलरी, या प्लास्टिक जैसे प्लेटे, कप, कटोरे, गिलास, कॉटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्ट्रॉ (1 जुलाई 2022 से मिठाई के डिब्बों की इर्द गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी०बी०सी० बैनर

प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झण्डे, कैण्डी स्टिक, आईसक्रीम की डंडिया, पॉलीस्टायरिन (थर्माकोल) की सजावटी समग्री) आदि चाहे वह किसी भी आकार व प्रकार के हो।

(ग) एकल उपयोग खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग कंटेनर चाहे किसी भी आकार, मॉप, प्रकार व रंग के हो जो पुनःचक्रित प्लास्टिक से बने हो व जो खाद्य, तरल पदार्थ को ढककर ले जाने व भण्डारित करने में उपयोग होता हो।

2- उक्त उपनियम कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी वस्तुओं में लागू नहीं होंगे।

(क) कोई भी व्यक्ति जानते हुए या अन्यथा की दशा में सार्वजनिक स्थल में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक को जो इन उपनियमों में प्रतिबंधित प्लास्टिक को न ही फेकेगा तथा उसका उपयोग भी नहीं करेगा।

(ख) हाटा बाजार संचालक, समस्त व्यवसायी, धार्मिक स्थलों व संस्थानों, सिनेमा घरों, मॉल, रेस्तरा कैंफे, मोबाईल फूड कार्नर, कैटर्स और अन्य स्थानों जैसे बाराजघर, पार्टी हॉल कार्यालय, संस्थान, फैक्ट्री स्वामी और प्राधिकरण उक्त उपनियमों का कड़ाई से पालन करने हेतु उत्तदायी होंगे, इसके साथ ही साथ उनके द्वारा जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण हेतु उनके परिसर में स्थान उपलब्ध कराया जायेगा व प्लास्टिक का एकत्रण कराया जायेगा। प्लास्टिक के एकत्रण के पश्चात उसको जिला पंचायत या अधिकृत ठेकेदार अपने परिवहन द्वारा नियत निस्तारण स्थल पर पृथकीकरण, कम्प्रेस करने के उपरान्त पुनर्चक्रण हेतु भेजेगी/भेजेगा।

4- बोतल बंद पानी की शीतल पेय हेतु पॉली ईथायलिन टेरेथलेट (पी0ई0टी0/पी0ई0टी0ई0) बोतलों के उत्पादनकर्ता विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के तहत परस्पर सहमत नियमों और शर्तों के अन्तर्गत एक ही खुदरा विक्री नेटवर्क के माध्यम से कमशः पोलिथिन, टेरेथलेट की बोतलों व प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस लेंगे, अथवा उनके उत्पाद द्वारा जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण परिवहन व सुरक्षित निस्तारण हेतु जिला पंचायत चम्पावत द्वारा किये गये खर्चों का भुगतान उनके द्वारा आवश्यक रूप से किया जायेगा।

5- ऐसी सभी उत्पादन इकाईयाँ जो बिन्दु सं0 1 ख में निर्दिष्ट उत्पाद बना रही हैं उन्हें इन उपनियमों के लागू होने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन बन्द करना होगा।

6- गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैंरीबैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जी0एस0एम0) से कम नहीं होगा।

7- 75 माइक्रोन (उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये जाने वाले परिवर्तन के अनुसार परिवर्तनीय) से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैंरीबैग व अन्य प्लास्टिक पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू होगा। ग्रामीण क्षेत्र के समस्त व्यवसायी, फैक्ट्री, प्रतिष्ठान, संस्थागत इकाई, घरों से उत्पन्न होने वाला प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक-पृथक एकत्रित करने की जिम्मेदारी स्वयं समस्त व्यवसायी, फैक्ट्री, प्रतिष्ठान, संस्थागत इकाई, घरों से उत्पादन कर्ता की होगी, जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट को निष्पत्तीकरण हेतु सुगमता से परिवहन किया जा सकें।

8- उपरोक्त उपविधियों का उल्लंघन करने की दशा में निम्नानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा।

उल्लंघनकर्ता	जुर्माने की धनराशि (रु0 में)
उत्पादनकर्ता	रु0 5.00 लाख
परिवहनकर्ता	रु0 2.00 लाख
खुदरा विक्रेता/विक्रेता	रु0 1.00 लाख
व्यक्तिगत उपयोग कर्ता	रु0 100.00
व्यवसायियों द्वारा उपयोग में लाये जाने पर	रु0 5,000.00 अथवा 500 प्रति पॉलीथीन
यदि पुनः उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो, इस दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता पर उपरोक्त का दोगुना जुर्माना आरोपित किया जायेगा।	

9- जिला पंचायत, चम्पावत के अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा निम्न नामित किये जाने वाले अधिकारी- कार्य अधिकारी, अभियन्ता, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कर अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता, प्रशासनिक अधिकारी, समस्त अनु० मुख्य लिपिक, समस्त सहायक लिपिक, समस्त क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, कर समाहर्ता/वसूली कर्ता जिला पंचायत चम्पावत उपनियमों /निर्देशों के कार्यान्वयन व जुर्माना आरोपित करने हेतु अधिकृत होंगे।

10- उपरोक्त अधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एकत्र किये जाने वाले जुर्माने की धनराशि जिला पंचायत के एक अलग खाते में जमा करायी जायेगी।

11- जिला पंचायत के अधिकृत अधिकारी/कर्मों को मौके पर यदि उल्लंघन कर्ता जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे जुर्माने की धनराशि का उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 180 के अन्तर्गत बिल प्रस्तुत किया जायेगा, तदुपरान्त भी 15 दिवस उपरान्त भी धनराशि जमा न की जाय तो जिला पंचायत नियमानुसार कार्यवाही करेगी।

12- जिला पंचायत चम्पावत द्वारा निर्मित उक्त उपविधियों के उल्लंघन किये जाने पर जिला पंचायत जुर्माने की उक्त धनराशि के बकायेदार व्यक्ति के विरुद्ध धारा 182 में दिये गये प्राविधान के तहत किसी क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय में वाद संस्थित कर सकेगी।

दण्ड

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 149 के अधीन कोई भी व्यक्ति इस नियम/विधि का उल्लंघन करता है तो जुर्माने से जो 1,000/- रु० तक हो सकता है, अथवा जैसा विहित किया जाय, दण्डनीय होगा, और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो वह एक ऐसे जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्ध की तिथि के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो (एक सौ रु०) तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय दण्डनीय होगा।

ह० (अस्पष्ट)

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चम्पावत।

ह० (अस्पष्ट)

अध्यक्ष,
जिला पंचायत, चम्पावत।

निधि यादव,
निदेशक।

निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड

16 जून, 2023 ई०

संख्या 270/933/जि०पंच०अ०को०/2022-23-

जिला पंचायत चम्पावत द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 106 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, चम्पावत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक शुल्क को विनियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु बनाई गई उपविधियां उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 द्वारा निर्मित उपविधियों में संशोधित उपविधियां बनाई गई हैं।

जिला पंचायत, चम्पावत की उपविधियों, की सार्वजनिक सूचना

जिला पंचायत चम्पावत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत सभी प्रकार की दुकानों एवं व्यवसायों आदि को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उपविधियाँ बनायी गई थी। जिनका प्रकाशन उत्तराखण्ड गजट में विज्ञापित संख्या 3447/इक्कीस-8/2013-14 दिनांक 30 सितम्बर, 2015 द्वारा हुआ है। इन उपविधियों में लाइसेंस की दरों में संशोधन प्रस्तावित किये जा रहे हैं। जो जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 25/03/2022 प्रस्ताव सं0 2 द्वारा पारित किया गया है। जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो प्रकाशन की तिथि के तीस दिन के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत, चम्पावत को भेज सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/सुझाव पर कोई विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। निर्धारित अवधि के दौरान आपत्तियों/सुझाव के बाद शासन से स्वीकृति के पश्चात उक्त दरें शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगी। लाइसेन्स प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिये बनेंगे।

क्र0 सं0	व्यवसाय	वर्तमान लाइसेन्स शुल्क	वार्षिक लाइसेन्स शुल्क	संसोधित दरें (वार्षिक लाइसेन्स शुल्क)
1	ठेकेदारी लाइसेन्स शुल्क:- (अ) प्रथम श्रेणी (20 लाख से ऊपर के कार्यों हेतु) (ब) द्वितीय श्रेणी (20 लाख तक के कार्यों हेतु)		2,000.00 1,500.00	2,500.00 2,000.00
2	मौस विक्रय:- (क) मौस विक्रय मछली, मुर्गा, भेड़, बकरी, सुअर आदि मिश्रित। (ख) मौस विक्रय मछली, मुर्गा, भेड़, बकरी, सुअर पृथक- पृथक विक्रय।		400 300	1,000.00 600.00
3	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित फैक्टिरियों एवं विभिन्न प्रकार की मशीनें:- 1- आरामशीन 2- बिस्कुट फैक्ट्री 3- धान, तेल मशीन, आटाचक्की पृथक मशीन। 4- धान, तेल मशीन, मशाला आदि एक ही मोटर पर प्रति मशीन। 5- लीसा फैक्ट्री 6- सीमेन्ट फैक्ट्री 7- शराब की दुकान 8- इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री 9- साबुन फैक्ट्री 10- जूस, आचार, मुरब्बा, अन्य लघु उद्योग। 11- प्लास्टिक सामग्री निर्माण कम्पनी। 12- मिनरल वाटर प्लॉट। 13- पेय पदार्थ, (कोल्ड ड्रिंक) कम्पनी। 14- केला राईपिंग प्लॉट। 15- राईस मिल।		1,500.00 500.00 500.00 300.00 7,000.00 6,000.00 30,000.00 3,000.00 400.00 3,000.00 — — — — 10,000.00	2,000.00 2,000.00 500.00 300.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00 3,000.00 500.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 10,000.00
4	अन्य व्यवसाय:- 1- परचून 10 हजार तक का सामान 2- परचून 10 हजार से अधिक का सामान 3- मिश्रित व्यवसाय छोटा 4- मिश्रित व्यवसाय बड़ा		300.00 500.00 500.00 700.00	300.00 500.00 500.00 1,000.00

5-	होटल व्यवसाय जहाँ ठहरने की व्यवस्था हो और 5 तक शयन कक्ष हो।	1,000.00	2,000.00
6-	होटल व्यवसाय जहाँ ठहरने की व्यवस्था हो और 5 से 10 तक शयन कक्ष हो।	2,000.00	3,000.00
7-	होटल व्यवसाय जहाँ ठहरने की व्यवस्था हो और 10 शयन कक्ष से अधिक हो।	3,000.00	5,000.00
8-	फर्नीचर की दुकान	1,000.00	2,000.00
9-	कारपेन्टर	1,000.00	1,500.00
10-	ईमारती लोहे की दुकान	1,000.00	1,000.00
11-	प्लास्टिक सामग्री की दुकान	800.00	1,000.00
12-	सस्तागल्ला विक्रय	500.00	500.00
13-	बालबर, दर्जी की दुकान	300.00	500.00
14-	बालबर, दर्जी की दुकान 2 से अधिक	—	1,000.00
15-	बर्तन की दुकान 50 हजार तक	—	500.00
16-	बर्तन की दुकान 50 हजार से अधिक	—	600.00
17-	कपड़े की सामान्य दुकान 50 हजार तक	—	500.00
18-	कपड़े की सामान्य दुकान 50 हजार से अधिक	—	600.00
19-	रेडिमेड की दुकान	500.00	1,000.00
20-	आभूषण की छोटी दुकान	300.00	500.00
21-	आभूषण की बड़ी दुकान	500.00	1000.00
22-	किताबें/स्टेशनरी की दुकान	500.00	600.00
23-	मेडिकल स्टोर छोटा	300.00	600.00
24-	मेडिकल स्टोर बड़ा	500.00	1,000.00
25-	दवाईयों के थोक विक्रेता	—	1,500.00
26-	पेट्रोल पम्प	4,000.00	5,000.00
27-	कृषि उपकरण व बीज भण्डार	300.00	600.00
28-	विजली समग्री एवं मरम्मत की दुकान	300.00	600.00
29-	सीमेन्ट की दुकान	2,000.00	2,500.00
30-	लोहा, सिमेन्ट की सम्मिलित दुकान	2,500.00	3,000.00
31-	लोहार एवं बढई की दुकान	300.00	300.00
32-	फेरी व्यवसाय कपड़ा, वर्तन आदि।	700.00	700.00
33-	फल/सब्जी विक्रय	300.00	300.00
34-	फल/सब्जी थोक विक्रय	—	800.00
35-	हार्डवेयर/पेन्ट	1,000.00	1,200.00
36-	थोक विक्रेता परचून	1,000.00	1,500.00
37-	हकीम, वैद्य, मेडिकल प्रैक्टिशनर एवं क्लिनिक	500.00	1,000.00
38-	ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय एवं टूर एण्ड ट्रेवल्स	3,000.00	4,000.00
39-	फोटोस्टेट मशीन	300.00	400.00
40-	टेलीविजन/मोबाईल/इलैक्ट्रॉनिक्स सामग्री	500.00	1,000.00
41-	घड़ी विक्रय एवं रिपेयर	200.00	200.00
42-	मोटर मैकेनिक	300.00	500.00
43-	साईकिल मरम्मत	300.00	400.00
44-	साईकिल विक्रय	500.00	1,000.00
45-	स्टोन कैरियर	5,000.00	5,000.00
46-	कोल्हू	1,000.00	1,000.00
47-	पीपीसी0ओ0	300.00	300.00
48-	वाहन सर्विस सेन्टर	1,000.00	1,500.00
49-	धर्मकाटा	500.00	1,000.00
50-	पोल्ट्रीफार्म	700.00	1,000.00

51-	मछली पालन	300.00	500.00
52-	नर्सिंग होम 10 बेड तक	1,000.00	2,000.00
53-	नर्सिंग होम 10 बेड अधिक	2,000.00	3,000.00
54-	ईट के थोक व्यापारी	4,000.00	5,000.00
55-	ईट के फुटकर बेचने पर	3,000.00	4,000.00
56-	पिक्चर हॉल/वीडियो फिल्म मेकर	2,000.00	3,000.00
57-	सब्जी के थोक विक्रेता	500.00	1,000.00
58-	जूते की दुकान	300.00	500.00
59-	प्रिंटिंग प्रेस	500.00	1,000.00
60-	फोटो स्टूडियो/वीडियो फिल्म मेकर	500.00	800.00
61-	मिनी राईस प्लॉन्ट	5,000.00	5,000.00
62-	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/ट्रेनिंग सेंटर	1,000.00	1,500.00
63-	टैन्ट हाउस	1,000.00	2,000.00
64-	रुई धुनाई मशीन/रजाई-गद्दा	500.00	1,000.00
65-	ईट भट्टा	8,000.00	10,000.00
66-	खाद/रासायनिक दवाओं का विक्रेता	500.00	600.00
67-	रिक्सा प्रति /ई-रिक्सा	75.00	200.00
68-	मैरिज हॉल	3,000.00	4,000.00
69-	मिठाई की दुकान बड़ी	500.00	1,000.00
70-	मिठाई की दुकान छोटी	300.00	500.00
71-	भोजनालय छोटा	300.00	500.00
72-	भोजनालय बड़ा	500.00	1,000.00
73-	पान, बीड़ी, सिगरेट विक्रेता	200.00	300.00
74-	ठेले/सब्जी फल व्यवसायी	150.00	300.00
75-	गत्ता मिल	500.00	1,000.00
76-	सैटरिंग सामग्री	1,500.00	2,000.00
77-	बिल्डर्स/निर्माण कम्पनी	3,500.00	4,500.00
78-	कम्प्यूटर सामग्री	500.00	1,000.00
79-	गिफ्ट सेंटर	300.00	500.00
80-	मार्बल स्टोन दुकान	3,000.00	4,000.00
81-	चूड़ी,चरेऊ एवं सौन्दर्य सामग्री (विसातखाना)	300.00	500.00
82-	चाय की दुकान	150.00	200.00
83-	अण्डे के थोक विक्रेता	300.00	1,000.00
84-	बैल्डिंग मशीन	500.00	800.00
85-	बियर बार	8,000.00	10,000.00
86-	खनन व्यवसाय (पट्टाधारक)	15,000.00	20,000.00
87-	स्टोन केशर मशीन	15,000.00	20,000.00
88-	शोरूम दो पहिया वाहन	8,000.00	10,000.00
89-	शोरूम चार पहिया वाहन	10,000.00	15,000.00
90-	भूसा स्टोर	700.00	1,000.00
91-	जूता बनाने की दुकान	350.00	600.00
92-	रेता बजरी खनन व्यवसाय	5,000.00	7,000.00
93-	डी0जे0	700.00	1,000.00
94-	प्लाईवुड	1,500.00	1,500.00
95-	कमीशन एजेंट	3,000.00	3,000.00
96-	हवा मशीन	400.00	500.00
97-	कबाड़ (कबाड़ी की दुकान)	3,000.00	3,000.00
98-	खराद मशीन	700.00	1,000.00
99-	टायर डीलर	3,000.00	3,000.00
100-	ब्यूटी पार्लर	300.00	500.00

101-	शराब के गोदाम		
	(अ) देशी शराब	25,000.00	25,000.00
	(ब) विदेशी शराब	35,000.00	35,000.00
	(स) बियर	15,000.00	15,000.00
102-	मोबाईल टॉवर	6,000.00	6,000.00
103-	पेन्ट विक्रय	700.00	1,000.00
104-	काँकरी सामग्री	350.00	500.00
105-	स्टील, प्लॉस्टिक फर्नीचर	500.00	1,000.00
106-	पैथोलॉजी सेंटर	300.00	1,000.00
107-	थोक गल्ला विक्रय	1,500.00	1,500.00
108-	जन सुविधा केन्द्र (सी0एच0सी0 सेंटर)	—	500.00
109-	दूध डेयरी	—	1,000.00
110-	टूरिस्ट पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों राफिटिंग / पैराग्लाइडिंग आदि।	—	2,000.00
111-	जड़ी-बूटी, छिलका - गुलिया, झूला तेज पत्ता आदि के गोदाम।	—	3,000.00
112-	हॉटमिक्स प्लॉट	—	10,000.00
113-	वाटर प्लॉट छोटा	—	3,000.00
114-	ब्रोडबैंड इन्टरनेट	—	1,000.00
115-	सीमेन्ट, सरिया, टाइल्स आदि के गोदाम	—	3,000.00
116-	बॉक्स, अलमारी, उद्योग	—	1,000.00
117-	रंधामशीन	—	1,000.00
118-	गमला उद्योग	—	500.00
119-	डिस्पोजल गिलास/प्लेट/दोना आदि उद्योग (प्लास्टिक को छोड़कर)।	—	1,000.00
120-	कार श्रृंगार सेंटर	—	1,000.00
121-	मुर्गी चारा उद्योग	—	1,000.00
122-	सेकेंड हैंड वाहन शोरूम	—	2,000.00
123-	व्यायामशाला (जिम)	—	1,000.00
124-	बेकरी छोटी	—	500.00
125-	बेकरी उद्योग		2,000.00
126-	नमकीन उद्योग		500.00
5-	ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन संचालन:-		
1-	प्राइवेट टैक्सी/मैक्सी	1200.00	1,500.00
2-	प्राइवेट मिनी बस	15,00.00	2,000.00
3-	प्राइवेट बस	2,000.00	2,500.00
6-	ग्रामीण क्षेत्रों में भवन /व्यवसायिक भवनों /लघु उद्योग, उद्योगों का नक्शा पास शुल्क :-		
	(अ)-निजी भवन 1000 स्क्वायर फिट तक।	—	3,000.00
	(ब)-निजी भवन 1000 स्क्वायर फिट से अधिक।	—	4,000.00
	(स)-व्यवसाय/उद्योग हेतु भवन 1,000 स्क्वायर फिट तक।	—	5,000.00
	(द)-व्यवसाय/उद्योग हेतु भवन 1,000 स्क्वायर फिट से अधिक।	—	8,000.00

दण्ड

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 106 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, चम्पावत प्रत्येक ऊपर वर्णित व्यवसाईयों से अपेक्षा करती है कि वे प्रतिवर्ष अपने व्यवसायों के लिए 31 दिसम्बर तक व्यवसायिक लाइसेन्स जिला पंचायत, चम्पावत से प्राप्त कर लें, अन्यथा उसके पश्चात 25 प्रतिशत सरचार्ज सहित लाइसेन्स निर्गत किये जा सकेंगे। जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थदण्ड का भागी होगा, जो रू0 1,000 तक होगा। यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहा तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा, जो प्रतिदिन रू0 50 होगा। यदि अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया जाता है तो कारागार से दण्डित होगा, जो तीन माह का हो सकेगा।

भगवत पाटनी,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चम्पावत।

ज्योति राय,
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, चम्पावत।

ओमकार सिंह,
निदेशक।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 नवम्बर, 2023 ई० (कार्तिक 13, 1945 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था०नि०) देहरादून

जनपद-देहरादून में नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023

सूचना

30 अक्टूबर, 2023 ई०

पत्रांक 147/स्था०नि०/वि० पुनरीक्षण/2023-24-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या-680/रा०नि०आ०-3/1260/2023 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के द्वारा राज्य की समस्त नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-य क के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 2016 की धारा 12 ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, सोनिका, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था०नि०) जनपद देहरादून की समस्त नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों (नगर पालिका परिषद, हरबटपुर को छोड़कर) की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कराये जाने के निर्देश देती हूँ :-

कार्यक्रम	दिनांक	अवधि
1-(क)1 नागर निकायवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति तथा कार्यक्षेत्र आवंटन एवं तदसंबंधी जानकारी प्राप्त करना।	02.11.2023 से 06.11.2023 तक	05 दिन
2-प्रशिक्षण	07.11.2023 से 09.11.2023 तक	03 दिन
(ख)-संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि	14.11.2023 से 08.12.2023 तक	25 दिन

(ग)—प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना	09.12.2023 से 13.12.2023 तक	05 दिन
(घ)—प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डाटा एन्ट्री/फोटो स्टेट	14.12.2023 से 07.01.2024 तक	25 दिन
(ङ)—निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन	08.01.2024	—
(च)—निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य के निरीक्षण तथा दावे/आपत्ति दाखिल करने की अवधि	09.01.2024 से 15.01.2024 तक	07 दिन
(छ)—दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	16.01.2024 से 22.01.2024 तक	07 दिन
(ज)—पूरक सूचियों की डाटा एन्ट्री/फोटो स्टेट	23.01.2024 से 01.02.2024 तक	10 दिन
(झ)—निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन	02.02.2024	—

2—जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थानीय निकाय) द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की निकायों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित क्षेत्र के समस्त कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। सर्वसाधारण की जानकारी में यह तथ्य भी ला दिये जायेंगे कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध, अपील अधोहस्ताक्षरी को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर जो अपील की विषय वस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और यह अपील उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) नियम-20 (1) (2) के अधीन दायर की गयी है।

3—जनपद देहरादून की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की सन्दर्भ तिथि 01 जनवरी, 2024 निर्धारित की जाती है, जनपद की समस्त नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों (नगर पालिका परिषद हरबटपुर को छोड़कर) की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण किया जायेगा। अर्थात् पुनरीक्षण में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जायेगा, जिन्होंने 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। तैयार निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचनों में प्रयुक्त की जायेगी।

जनपद—देहरादून में नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम—2023

सूचना

30 अक्टूबर, 2023 ई0

पत्रांक 148/स्था0नि0/वि0 पुनरीक्षण/2023-24—राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या-679/रा0नि0आ0-3/1260/2023 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के द्वारा राज्य की समस्त नगर निगमों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद 243—य क के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 35 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, सोनिका, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0) जनपद देहरादून के नगर निगम, देहरादून एवं ऋषिकेश की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कराये जाने के निर्देश देती हूँ :-

कार्यक्रम	दिनांक	अवधि
1-(क)1 नागर निकायवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति तथा कार्यक्षेत्र आवंटन एवं तदसंबंधी जानकारी प्राप्त करना।	02.11.2023 से 06.11.2023 तक	05 दिन
2-प्रशिक्षण	07.11.2023 से 09.11.2023 तक	03 दिन
(ख)-संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि	14.11.2023 से 08.12.2023 तक	25 दिन
(ग)-प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना	09.12.2023 से 13.12.2023 तक	05 दिन
(घ)-प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डाटा एन्ट्री/फोटो स्टेट	14.12.2023 से 07.01.2024 तक	25 दिन
(ङ)-निर्वाचक नामावलियां के आलेख्य का प्रकाशन	08.01.2024	—
(च)-निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य के निरीक्षण तथा दावे/आपत्ति दाखिल करने की अवधि	09.01.2024 से 15.01.2024 तक	07 दिन
(छ)-दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	16.01.2024 से 22.01.2024 तक	07 दिन
(ज)-पूरक सूचियों की डाटा एन्ट्री/फोटो स्टेट	23.01.2024 से 01.02.2024 तक	10 दिन
(झ)-निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन	02.02.2024	—

2-जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थानीय निकाय) द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की निकायों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित क्षेत्र के समस्त कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। सर्वसाधारण की जानकारी में यह तथ्य भी ला दिये जायेंगे कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिष्पन्न के विरुद्ध, अपील अद्योहस्ताक्षरी को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर जो अपील की विषय वस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और एह अपील उत्तर प्रदेश नगर नगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) नियम-20 (1) (2) के अधीन दायर की गयी है।

3-जनपद देहरादून की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की सन्दर्भ तिथि 01 जनवरी, 2024 निर्धारित की जाती है, जनपद की नगर निगम, देहरादून एवं ऋषिकेश की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण किया जायेगा। अर्थात् पुनरीक्षण में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जायेगा, जिन्होंने 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। तैयार निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचनों में प्रयुक्त की जायेगी।

सोनिका,

जिला मजिस्ट्रेट/

जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0),

देहरादून।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 नवम्बर, 2023 ई0 (कार्तिक 13, 1945 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

आदेश

19 अक्टूबर, 2023 ई0

सं.76/उत्तराखण्ड-वि.स./45/2022/सी.ई.एम.एस.-III-यतः, उत्तराखण्ड राज्य की 45-गंगोलीहाट (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं. 464/उत्तरा0-वि0स0/2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी।

यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 45-गंगोलीहाट (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं. 2782/XXV-53/2022 देहरादून के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती रेखा, जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 45-गंगोलीहाट (अ0जा0) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती रेखा, को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तराखण्ड-वि.स./45/2022/सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती रेखा, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या 1256/29-(निर्वाचन व्यय लेखा)/2022 दिनांक 17.09.2022 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं0 891/XXV-22(II)/2008 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा अग्रेषित कर आयोग को सूचना दी गई कि उक्त नोटिस दिनांक 04.11.2022 को अभ्यर्थी के घर पर कोई भी मौजूद नहीं होने के कारण मकान के सहज दृश्य भाग पर नोटिस चस्पा कर साथ ही नोटिस की सूचना अभ्यर्थी के मो0 7466824255 पर व्हाट्सप के माध्यम से भी भेज दिया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या 484/29--(निर्वाचन व्यय लेखा)/2022 दिनांक 13.09.2023 के द्वारा अग्रेषित कर भेजी गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती रेखा, ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती रेखा, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 45-गंगोलीहाट (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती रेखा, निवासी ग्राम- पलतोड़ी, पोस्ट - बनकोट, तहसील- गणगौर, पिथौरागढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

बिनोद कुमार,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,

मस्तू दास,

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

उत्तराखण्ड।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan Ashoka Road New Delhi-110001ORDER

October 19, 2023

No. 76/Uttarakhand-LA/45/2022/CEMS-III--WHEREAS, the General Election to **45-Gangolihat (SC)** Legislative Assembly of Uttarakhand, 2022 was held vide Notification No. 464/Uttarakhand-LA/2022 dated 21st January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with **45-Gangolihat (SC)** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Pithoragarh, Uttarakhand and forwarded by the Chief Electoral Officer, Uttarakhand vide their letter No. 2782/XXV-53/2022, dated 22nd April, 2021, Smt. Rekha, a contesting candidate of Uttarakhand from **45-Gangolihat (SC)** Assembly Constituency of Uttarakhand, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer Pithoragarh, Uttarakhand and the Chief Electoral Officer, Uttarakhand, a Show-Cause notice, 76/Uttarakhand -LA/2022/45/CEMS-III dated 20.10.2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Rekha, for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 20.10.2022, Smt. Rekha, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was pasted on 04.11.2022 in front of the candidate house as no one was present in his house and notice was also served through whatsapp no. 7466824255. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Pithoragarh, vide its letter No.1256/29-(निर्वा.व्यय-लेखा)/2022 dated 17.09.2022; forwarded by Chief Electoral Officer, Uttarakhand, letter no.891/XXV-22(II)/2008 date 15.06.2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Pithoragarh, in his Supplementary Report forwarded vide its letter No. 484/29-(निर्वा.व्यय-लेखा)/2022 dated 13.09.2023 reported that Smt. Rekha, neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he neither furnished any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Rekha, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Rekha resident of Village-Paltori, Post- Bankot, Tehsil- Ganai, Pithoragarh, a contesting candidate from 45-Gangolihat(SC) Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,

Secretary,

Election Commission of India.

By Order,

MASTU DAS,

Assistant Chief Electoral Officer,

Uttarakhand.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 नवम्बर, 2023 ई0 (कार्तिक 13, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

शादी से पहले मेरा नाम शैक्षिक प्रमाण पत्रों में ताज पुत्री इरशाद खान था शादी के बाद अब मेरा नाम आरिफा ताज पत्नी मोहम्मद सुभान खान, नूर मंजिल बसेड़ी रोड, निकट आर्य समाज मंदिर आदर्श कालोनी वार्ड नंबर 6 लक्सर (हरिद्वार) है अब मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

आरिफा ताज पत्नी मोहम्मद सुभान खान,
निवासी नूर मंजिल बसेड़ी रोड, निकट आर्य
समाज मंदिर आदर्श कालोनी वार्ड नंबर 6
लक्सर (हरिद्वार)

सूचना

GENERAL public is informed that I have changed my name from MUKESH CHAND (old name) to MUKESH CHANDRA JHALDIYAL (new name) and in future I should be known as MUKESH CHANDRA JHALDIYAL (new name)

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

MUKESH CHANDRA JHALDIYAL
R/o 118, Lane No. 8, Vijay Park
Extension, Dehradun.

कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

सार्वजनिक सूचना

नगर निगम, रुद्रपुर पार्किंग शुल्क उपविधि

01 जून, 2023 ई0

पत्रांक 169/2023-24—नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 172(1) (ख) के अंतर्गत नगर निगम रुद्रपुर के सीमान्तर्गत वाहनों को सड़क के किनारे खड़े करने पर पार्किंग शुल्क आरोपित करने हेतु नगर निगम बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार पार्किंग/रजिस्ट्रेशन शुल्क दरें निर्धारित की गयी हैं। अतः नगर निगम रुद्रपुर की अधिसूचना क्षेत्र की परिधि में आने वाली सामान्य जनता या फिर उन व्यक्तियों, जिन पर प्रस्तावित शुल्क के प्रभाव पड़ने की सम्भावना की जाती है, उन नागरिकों/संस्थाओं से अपना आपत्ति/अनापत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक समाचार-पत्र में सूचना प्रकाशित की जाती है समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के दिनांक से अंदर 30 दिवस के नगर आयुक्त, नगर निगम को संबोधित करते हुये, नगर निगम कार्यालय के कक्ष सं0 12 में स्थापित ड्रॉप बाक्स में प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक डाले जा सकते हैं नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (क) यह उपनियम नगर निगम, रुद्रपुर की सीमान्तर्गत वाहनों जो नगर निगम, रुद्रपुर सीमान्तर्गत सड़क किनारे (ऐसे वाहन जो केवल घायलों, एवं बीमारों या मृतकों को निःशुल्क लाने ले जाने के लिये अभिप्रेत हो व ऐसे वाहन जिसके वास्तविक व्यापारी केवल विक्रय के प्रयोजनार्थ अपने पास रखते हों और जो प्रयोग न होती हों) को छोड़ कर, खड़े करने पर शुल्क उपनियम वर्ष 2022 कहलायेगी।
- (ख) यह उपनियम गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2-परिभाषाएं -

- (क) "नगर निगम" से तात्पर्य नगर निगम, रुद्रपुर व उसकी सीमा से है।
- (ख) "नगर निगम" से तात्पर्य नगर निगम, रुद्रपुर के नगर आयुक्त से है।
- (ग) "अधिनियम" तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) से है।
- (घ) "पार्किंग कार्ड" से तात्पर्य नगर निगम, रुद्रपुर की सीमान्तर्गत वाहनों को सड़क किनारे खड़े करने पर शुल्क भुगतान कर प्राप्त कार्ड से है।
- (ङ) "अनुज्ञा अधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम रुद्रपुर के नगर आयुक्त एवं उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी यथा सहायक नगर आयुक्त/कर अधीक्षक आदि से है।
- (च) वर्ष-से तात्पर्य इस उपनियम के अंतर्गत पार्किंग कार्ड की अवधि प्रति वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च के लिये वैध होगी।
- 3- नगर निगम रुद्रपुर की सीमा के अंतर्गत सड़क किनारे वाहन पार्क तभी किया जा सकता है जब वह नगर निगम रुद्रपुर कार्यालय में निर्धारित प्रारूप (क) में आवेदन कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर पार्किंग कार्ड प्रारूप (ख) प्राप्त करेगा।
- 4- प्रत्येक व्यक्ति/आम जनमानस जो नगर निगम सीमान्तर्गत निवास करते हैं उन्हें अपने वाहनों को सड़क पर पार्क किये जाने पर वाहनों का वार्षिक पार्किंग शुल्क नगर निगम, कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि 31 मार्च तक वैध रहेगा।

- 5- वाहनों को सड़क किनारे पार्क किये जाने हेतु इन उपविधियों के अधीन, नगर निगम रुद्रपुर कार्यालय से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह तक पार्किंग कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 6- प्रत्येक वाहनों का शुल्क उन वाहन के 1- मॉडल 2-नम्बर प्लेट तथा दुपहिया वाहन (निजी) 3-चार पहिया वाहन (निजी), 4-चार पहिया वाहन (टैक्सी), 5-मैजिक, बड़े वाहन जैसे-बस, ट्रक आदि के आधार पर लिया जायेगा। इसके लिए आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित वार्षिक शुल्क जमा करना होगा।

क्र०सं०	वाहनों के प्रकार	पार्किंग शुल्क प्रतिवर्ष	पार्किंग शुल्क प्रतिवर्ष	मार्च माह से अप्रैल माह के पश्चात विलम्ब शुल्क प्रतिमाह
01	दुपहिया वाहन	रु0 200		100 प्रतिमाह
02	चौपहिया वाहन निजी	10लाख तथा 10लाख से अधिक लक्जरी कार का 0.10 प्रतिशत	10लाख तक तथा 10लाख से कम साधारण कार का 0.08 प्रतिशत	500 प्रतिमाह
03	चौपहिया वाहन टैक्सी, मैजिक	800		800 प्रतिमाह
04	बड़े वाहन जैसे- बस, ट्रक आदि	1000		1000 प्रतिमाह

- 7- वाहन के स्वामी को प्रत्येक वर्ष अप्रैल अथवा इससे पूर्व ही वार्षिक शुल्क के नवीनीकरण के लिये आवेदन निर्धारित शुल्क सहित प्रेषित करना होगा। विलम्ब से प्रेषित नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र पर निर्धारित प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा।
- 8- प्रत्येक वाहन के शुल्क भुगतान के पश्चात पार्किंग कार्ड जारी किया जायेगा, जो वाहन स्वामी को अपने गाड़ी में चिपकाना होगा।

दण्ड(शस्ति)

नगर निगम, रुद्रपुर की सीमान्तर्गत खड़े वाहनों का रजिस्ट्रेशन न करने पर एवं इस नियमावली की अवहेलना होने पर वाहन स्वामी दण्ड का भागी होगा, जो 1-रु0 5000.00 तक हो सकता है एवं अवज्ञा जारी रहने की दशा में प्रतिदिन रु0 200 तक का अतिरिक्त दण्ड देय होगा।

विशाल मिश्रा,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, रुद्रपुर।

रामपाल सिंह,
महापौर,
नगर निगम, रुद्रपुर
उधमसिंह नगर।